12.04 hrs.

CALLING ATTENTION TO A MATTER OF

URGENT PUBLIC IMPORTANCE

Need for a financial package to Bihar for developmental works in the State

Title: Regarding statement by the Prime Minister in response to the clarificatory questions asked by members on 12th December, 2003 on the statement made by the Minister of State in the Ministry of Planning responding to the attention called by Dr. Raghuvansh Prasad Singh to the need for a financial package to Bihar for developmental works in the state. (continued - concluded).

MR. SPEAKER: Now, we shall take up item No.22 − Calling Attention regarding need for a financial package to Bihar for developmental works in the state, the Prime Minister to make a statement in response to the clarificatory questions asked by the Members on 12th December, 2003. Hon. Prime Minister.

डॉ. रघुवंश प्रसाद सिंह (वैशाली) : अध्यक्ष जी, मैं प्रधान मंत्री जी का ध्यान संक्षेप में जो असली मुद्दा था उसकी ओर दिलाना चाहता हूं। बिहार के 8 करोड़ गरीब आदमियों के लिए माननीय प्रधान मंत्री जी अगर न्याय कर पातेâ€¦ (व्यवधान) इसमें 100 जिले देश से चुने गये हैं लेकिन बिहार का एक भी जिला नहीं है। बिजली के जैनरेशन में भारत सरकार ने एक भी पैसा नहीं दिया है जोकि सबसे महत्वपूर्ण मसला है।â€¦ (व्यवधान)

MR. SPEAKER: Please sit down. The hon. Prime Minister is on his legs. He will make a statement. प्रधान मंत्री जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट हैं।

प्रधान मंत्री (श्री अटल बिहारी वाजपेयी) : अध्यक्ष महोदय, बिहार की विकास संबंधी समस्याओं के बारे में माननीय सांसदों द्वारा व्यक्त चिंताओं के संबंध में मुझे मालूम हुआ और मैं यहां आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि बिहार सहित कुछ क्षेत्रों की गरीबी और पिछड़ेपन की समस्या से प्रभावी रूप से निपटने का मुद्दा हमारा ध्यान आकर्ति करता रहा है तथा हमने दसवीं पंचवर्षीय योजना में राट्रीय सम विकास योजना (RSVY) शुरु की है, जिसमें बिहार के लिए एक विशेा आर्थिक पैकेज की व्यवस्था है। इस योजना के अन्तर्गत महत्वपूर्ण क्षेत्रों की जिन परियोजनाओं पर ध्यान देने की जरूरत है, उनका पता लगाया गया है और उनके कार्यान्वयन के लिए पूरी केन्द्रीय सहायता दी जाएगी।

जैसा कि आपको मालूम ही है, गाडगिल-मुखर्जी फार्मूला के अनुसार राज्य की योजानाओं को वित्त-पोाति करने के लिए केन्द्रीय सहायता दी जाती रही है जिसके अन्तर्गत जनसंख्या और प्रति व्यक्ति आय को 58 प्रतिशत महत्व दिया जाता है, जिससे बिहार जैसे राज्यों को मदद मिलती है। इसके अलावा, राज्य योजनाओं को िवत्त-पोाति करने के लिए चयनित अनेक कार्यक्रमों और विशेा परियोजनाओं के लिए भी अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। वास्तव में, चालू र्वा के लिए बिहार के 3320 करोड़ रुपए के योजना परिव्यय का 83 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता के रूप में वित्त-पोाति किया गया है।

अब मैं बिहार के उन महत्वपूर्ण क्षेत्रों, जिनके बारे में माननीय सांसदों ने सदन का ध्यान आकृट किया है, के विकास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों को विस्तारपूर्वक बताता चाहूंगा।

सड़कें

बिहार में 3408 कि.मी. राट्रीय राजमार्गों में से, 723 कि.मी. को राट्रीय राजमार्गों विकास परियोजना के अन्तर्गत 4 लेन वाली सड़कों के विकास के लिए शामिल किया गया है। इसमें स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना के अंतर्गत राट्रीय राजमार्ग संख्या-2 की 206 कि.मी. सड़क और पूर्वी-पश्चिमी कोरीडोर की 517 कि.मी. लम्बी सड़क शामिल है। शेा सड़कों का विकास राज्य सरकार और अन्य एजेंसियों के माध्यम से किया जा रहा है। राट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत राज्य राजमार्गों को उन्नत और सुदृढ़ बनाने के लिए एक विशेा परियोजना को वित्त-पोाति किया जा रहा है। प्रमुख जिला सड़कों/ अन्य जिला सड़कों का सुधार नाबार्ड के ग्रामीण आधारभूत प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की निधियों का इस्तेमाल करके किया जाएगा। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत ग्रामीण सड़कों के विकास के लिए बिहार को प्रतिर्वा 150 करोड़ रुपए की धनराश आवंटित की जाती है। दुर्भाग्यवश, र्वा 2002-2003 में राज्य सरकार की व्यय की धीमी गति के कारण कोई निधियां जारी नहीं की जा सकीं।

बिजली

इस समय बिहार की बिजली की अधिकांश जरूरतें केन्द्रीय उपयोगी सेवाओं से पूरी की जा रही है। इसके अतिरिक्त, नेशनल थर्मल पावर कार्पोरेशन दसवीं/ ग्यारहवीं योजना अवधियों के दौरान बिहार में लगभग 18,700 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से 4480 मेगावाट की कुल क्षमता वाली तीन विशाल परियोजनाओं को शुरु करने की योजना बना रहा है। इसके अलावा, इस क्षेत्र के लिए पूर्वोत्तर की हाइडल परियोजनां की अतिरिक्त बिजली की उपलब्ध होगी। समस्या बिजली की उपलब्धता की नहीं है, बल्कि उसे आधिक मात्रा में खपाने की बिहार की क्षमता की है। इसलिए, राट्रीय सम विकास योजना (RSVY) के अन्तर्गत राज्य में 365 करोड़ रुपए की लगात से सब-ट्रांसमिशन सिस्टम को सुदृढ़ करने की एक परियोजना शुरु की जा रही है। इसके अतिरिक्त त्वरित विद्युत विकास और सुधार कार्यक्रम (एपीडीआरपी) के अन्तर्गत 765 करोड़ रुपए की लागत वाले विद्युत वितरण आधारभूत ढांचे के सुधार की योजनाओं को अंतिम रूप दे दिया गया है जिन्हें दो सालों के अन्दर पूरा किया जाएगा। इस निवेश से बिहार राज्य अधिक बिजली का इस्तेमाल करके अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार ला सकेगा। कुछ सदस्यों ने राज्य द्वारा संचालित विद्युत केन्द्रों के लो प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) का जिक्र किया है। एन.टी.पी.सी., मुजफ्फरपुर पावर स्टेशन के अधिग्रहण करने, इसके आधुनिकीकरण पर निवेश करने और प्लांट लोड फैक्टर (पीएलएफ) में सुधार लाने के लिए तैयार है बर्शेत कि राज्य सरकार इसके लिए सहमत हो।

सिंचाई और बाढ़

हालांकि सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण राज्य के विाय हैं, फिर भी, केन्द्र सरकार इस समस्या के प्रति सचेत है और विभिन्न योजनाओं के जरिए राज्य की मदद कर रही है। नेपाल से निकलने वाली कमला, बागमती और कोसी जैसी नदियों के कारण उत्तरी बिहार की बाढ़ की समस्याओं को देखते हुए, भारत सरकार साप्ता कोसी और सन कोसी नदियों पर जलाशयों के निर्माण हेतु जांच शुरु करने और परियोजना-रिपोर्ट तैयार करने के लिए नेपाल के साथ पहले ही एक समझौता कर चुकी है। अन्य दो नदियों पर भी इसी प्रकार की परियोजनाएं शुरु करने के लिए विचार-विमर्श चल रहा है। केन्द्र सरकार ने बाढ़ नियंत्रण क्षेत्र में कोसी और गंडक तटबंधों का रख-रखाव

करने, उन्हें बाढ़ से अभेद्य बनाने, नेपाल क्षेत्र में तटबंधों का विस्तार करने और भू-कटाव को रोकने हेतु कार्यों के लिए चार योजनाओं को भी स्वीकृत किया है। राज्य सरकार को चाहिए कि वह इन योजनाओं का लाभ उठाए और उपलब्ध निधियों का पूर्णतया इस्तेमाल करे।

त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के अन्तर्गत, केन्द्र सरकार ने लगभग तीन लाख हैक्टेयर भूमि की अतिरिक्त सिंचाई क्षमता का सृजन करने के लिए पहले ही सात परियोजनाएं अनुमोदित कर दी हैं। किन्तु पिछले दो सालों में राज्य सरकार द्वारा धन निकासी निर्धारित सीमा से काफी कम रही है। राज्य सरकार को चालू परियोजनाओं को पूरा करने के लिए आवंटित निधियों का पूरा-पूरा इस्तेमाल करना चाहिए।

केन्द्र सरकार, राट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत 294 करोड़ रुपए की लागत वाली पूर्वी गंडक नहर प्रणाली के पुनरुद्धार की परियोजना का पूरा वित्त-पोाण करने के लिए भी सहमत हो गई है। इस परियोजना से लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि की सिंचाई क्षमता बहाल होगी जो नहर प्रणाली में गाद भरने और उसकी जीर्ण-शीर्ण अवस्था के कारण नट हो जाती थी।

राट्रीय सम विकास योजना के अन्तर्गत दो मिलियन हेक्टेयर भूमि की सिंचाई करने के लिए दस लाख सतही ट्यूबवैल (शैलो ट्यूबवैल्स) लगाने का एक कार्यक्रम शुरु किया जा रहा है। मुझे बताया गया है कि इस वर्ा के अंत तक एक लाख ट्यूबवैल लगा दिए जाएंगे। मुझे विश्वास है कि इस कार्यक्रम से बिहार के लाखों किसानों को फायदा पहुंचेगा और कृाि से उनकी आय में सुधार होगा। बिहार के चार जिलों में इनकी बागवानी अर्थव्यवस्था में सुधार लाने के लिए आम, लीची, मखाना फसलों और मसालों की खेती के विकास हेतु विशेा परियोजनाएं शुरु की जा रही हैं।

रेलवे

बिहार में नई रेल लाइनों के निर्माण की तेरह, अमान परिवर्तन की दस, दोहरी रेल लाइनें बिछाने की पंद्रह और विद्युतीकरण की दो परियोजनाएं शुरू की गई हैं।

राट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीवाई)

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, 10वीं योजना के दौरान 2531.35 करोड़ रुपए की लागत की निम्नलिखित परियोजनाओं का कार्यान्वयन हेतु चयन किया गया है -

<u>परियोजनाओं का नाम राशि (करोड़ रुपए)</u>

1. दस लाख सतही ट्यूबवैल 578.28

   कार्यक्रम (सब्सिडी घटक)

2. बिहार में सब-ट्रांसमिशन 365.00

सिस्टम का सुदृढ़ीकरण

3. बिहार में राज्य राजमार्गों 846.29

का विकास

4. पूर्वी गंडक नहर का पुनरुद्धार 294.00

5. बागवानी का विकास (सब्सिडी घटक) 36.78

6. एकीकृत वन प्रबन्धन 351.00

7. एकीकृत जलाशय विकास 60.00

कुल 2531.35

मैं आपको आश्वस्त कर दूं कि योजना आयोग की वचनबद्धता के अनुसार, इन परियोजनाओं, जिन का व्यापक विचार-विमर्श के बाद चयन किया गया है, के कार्यान्वयन को अत्यधिक प्राथमिकता दी जाएगी और इनके लिए निधियों की कोई कमी आड़े नहीं आएगी। दसवीं योजना के दौरान प्रति वर्ा 1000 करोड़ रुपए की दर से केन्द्रीय सहायता दी जाएगी बर्शेत कि इसका वास्तविक उपयोग किया जाए। परियोजनाओं का समय पर कार्यान्वयन करने में केन्द्रीय एजेंसियों को शामिल किया जाएगा।

पिछड़ा जिला पहल के अंतर्गत, चरमपंथवाद से प्रभावित बिहार के आठ जिलों को शामिल किया गया है। इन जिलों को तीन वर्ाों के लिये प्रत्येक के प्रति वर्ा 15 करोड़ रुपये की दर से अनुदान मिलेगा। मेरा ध्यान इस पहल के सामान्य घटक से बिहार और उड़ीसा को अलग रखने की ओर आकृट किया गया है। मैं आप सभी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि इन दो राज्यों के पात्र जिलों के भी इस कार्यक्रम के अंतर्गत शामिल किया जायेगा।

इस प्रकार, बिहार की विकास संबंधी समस्याओं से निपटने के लिये बहु-आयामी प्रयास किये जा रहे हैं। तथापि, माननीय सदस्य मेरी इस बात से सहमत होंगे कि परियोजना के सफल कार्यान्वयन के लिये अनुकूल माहौल, प्रभावी प्रशासन और सभी संबंधितों द्वारा शीघ्र निर्णय लेने की जरूरत होती है। राज्य सरकार को परियोजनाओं के समय पर पूरा करने के लिये अपने तंत्र को चुस्त दुरुस्त करने की जरूरत है ताकि विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्य को आबंटित निधियों का उपयोग हो और इसके वांछित लाभ राज्य और अंतत: लाभार्थियों को मिल सकें। राज्य और केन्द्र सरकार के संयुक्त प्रयासों से मुझे उम्मीद है कि राट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत विशेा योजना के माध्यम से की गई पहल से राज्य में विकास प्रक्रिया को गति प्रदान करने में मदद मिलेगी।